शहरी-ग्रामीण भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता का पुनर्गठन

UPSC प्रासंगिकता GS II: शासन, स्थानीय स्वशासन, सेवा वितरण **GS III:** सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता **GS IV:** कल्याणकारी वितरण की नैतिकता, गरिमा, जिम्मेदारी

चर्चा में क्यों? स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के शुभारंभ के एक दशक से अधिक समय बाद, भारत ने लगभग सार्वभौमिक 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) दर्जा प्राप्त कर लिया है। हालांकि, विशेष रूप से ग्रामीण और उप-शहरी (peri-urban) क्षेत्रों में मल कीचड़ प्रबंधन (faecal sludge management) के आसपास उभरती चिंताओं ने नीतिगत ध्यान को SBM-ग्रामीण चरण II और ODF प्लस के तहत स्वच्छता परिणामों को बनाए रखने की ओर स्थानांतरित कर दिया है।

पृष्ठभूमि: पहुंच से स्थिरता तक 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता के प्रति भारत की ऐतिहासिक उपेक्षा को निर्णायक रूप से समाप्त किया। ग्रामीण भारत में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण और सार्वभौमिक ODF घोषणाओं के साथ, मिशन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ पहुँचाए:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम
- महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा
- बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन

हालांकि, इस बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाली सफलता ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत कमी को भी उजागर किया: शौचालय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, और इसे प्रबंधित करने के लिए सुरक्षित प्रणालियों के बिना, स्वच्छता लाभों के उलटने का जोखिम रहता है। अधिकांश ग्रामीण परिवार सेप्टिक टैंकों और गड्ढों पर निर्भर हैं, जो अंततः भर जाते हैं। सुरक्षित कीचड़ निकालने (desludging) और उपचार प्रणालियों के अभाव में, मल अपशिष्ट अक्सर मिट्टी, भूजल और जल निकायों को दूषित करता है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा दोनों को खतरा होता है।

SBM-G चरण II के तहत ODF प्लस की ओर बदलाव इस अंतर को पहचानते हुए, SBM-ग्रामीण चरण II ने स्वच्छता नीति को केवल निर्माण से पूर्ण स्वच्छता सेवा वितरण की ओर पुनर्गठित किया। ODF प्लस निम्नलिखित पर केंद्रित है:

- मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSM)
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
- व्यवहारगत स्थिरता
- एंड-टू-एंड स्वच्छता मूल्य श्रृंखला

अक्टूबर 2025 तक, लगभग 97% गांवों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। फिर भी, FSM सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है, विशेष रूप से:

- उप-शहरी क्षेत्रों में
- उपचार बुनियादी ढांचे की कमी वाले गांवों में
- अनौपचारिक और असुरक्षित कीचड़ निकालने की प्रथाओं पर निर्भर क्षेत्रों में

शहरी-ग्रामीण भागीदारी: सतारा मॉडल महाराष्ट्र का सतारा जिला एक अभिनव और स्केलेबल समाधान प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताएं

- सतारा शहर के कम उपयोग किए जाने वाले मल कीचड़ उपचार संयंत्र (65 KLD क्षमता) को पास के गांवों के लिए खोल दिया गया।
- ग्राम पंचायतों ने असुरक्षित, तदर्थ प्रथाओं की जगह हर पांच साल में अनुसूचित रूप से कीचड़ निकालने (scheduled desludging) को संस्थागत रूप दिया।
- लागत की वसूली एक मामूली स्वच्छता कर के माध्यम से की जाती है, जिससे सामर्थ्य और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच औपचारिक समझौते अधिकृत वाहनों को बिना किसी शुल्क के उपचार सुविधाओं तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।

IAS-PCS Institute
Result
रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com
9235313184, 9235440806

शहरों से दूर के गांवों के लिए, वैकल्पिक मॉडल अपनाए गए:

- क्लस्टर-स्तरीय मल कीचड़ उपचार संयंत्र
- निजी ऑपरेटरों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को शामिल करने वाले PPP मॉडल यह दर्शाता है कि ग्रामीण स्वच्छता विकेंद्रीकृत और पेशेवर रूप से प्रबंधित दोनों हो सकती है।

यह मॉडल क्यों महत्वपूर्ण है?

- **दक्षता:** कम उपयोग किए गए शहरी बुनियादी ढांचे का अनुकूलन करता है।
- **समानता:** ग्रामीण आबादी तक स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करता है।
- **स्थिरता:** एकमुश्त निर्माण से जीवनचक्र प्रबंधन (lifecycle management) की ओर बदलाव लाता है।

- **शासन नवाचार:** पंचायती राज संस्थानों (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच समन्वय को मजबूत करता है।
- **नैतिक शासन:** गरिमा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बनाए रखता है।

स्केलिंग में प्रमुख चुनौतियां

1. संस्थागत विखंडन

- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच कमजोर समन्वय।
- स्पष्ट जवाबदेही के बिना जिम्मेदारियों का दोहराव।

2. क्षमता की कमी

- ग्राम पंचायत स्तर पर सीमित तकनीकी विशेषज्ञता।
- FSM योजना और अनुबंध प्रबंधन में अपर्याप्त प्रशिक्षण।

3. वित्तीय स्थिरता

- गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता करों के प्रति प्रतिरोध।
- पूर्वानुमानित राजस्व धाराओं के बजाय योजना-आधारित वित्त पोषण पर निर्भरता।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

4. अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता

- अनियमित कीचड़ निकालने वाले ऑपरेटरों पर निरंतर निर्भरता।
- स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए व्यावसायिक खतरे और गरिमा का उल्लंघन।

5. व्यवहारगत और सामाजिक चुनौतियां

- समय-समय पर कीचड़ निकालने के बारे में कम जागरूकता।
- यह धारणा कि शौचालय निर्माण के साथ स्वच्छता समाप्त हो जाती है।

6. पर्यावरणीय जोखिम

- असुरक्षित डंपिंग भूजल और कृषि भूमि को दूषित करती है।

- दीर्घकालिक पारिस्थितिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम।

आगे की राह: टिकाऊ ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करना

संस्थागत उपाय

- SBM-G दिशानिर्देशों के भीतर शहरी-ग्रामीण स्वच्छता अभिसरण को औपचारिक रूप देना।
- PRIs, ULBs और जिला प्रशासन की भूमिकाओं को स्पष्ट करना।
- पंचायत समितियों को समन्वय मंच के रूप में मजबूत करना।

क्षमता निर्माण

- FSM पर स्थानीय सरकारों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण।
- जिला स्तरीय स्वच्छता सहायता इकाइयों का निर्माण।

वित्तीय सुधार

- पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी के साथ स्वच्छता करों को बढ़ावा देना।
- परिणाम-आधारित वित्त पोषण और व्यवहार्यता अंतर सहायता (viability gap support) की संभावना तलाशना।

समावेशी PPP मॉडल

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- सुरक्षा और गरिमा मानदंडों के साथ निजी ऑपरेटरों को विनियमित करना।
- स्थानीय रोजगार के लिए SHG-नेतृत्व वाले स्वच्छता उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता

- सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियानों को "शौचालय उपयोग" से "स्वच्छता जीवनचक्र" की ओर स्थानांतरित करना।
- स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों पर सामुदायिक जुड़ाव।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय

- सह-उपचार (co-treatment) और विकेंद्रीकृत उपचार समाधानों को बढ़ावा देना।
- जल सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन के साथ स्वच्छता योजना को एकीकृत करना।

नैतिक और शासन आयाम स्वच्छता केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है बल्कि राज्य की एक नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक शासन के लिए आवश्यक है:

- मानवीय गरिमा की रक्षा करना।
- श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण का संरक्षण करना।
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए योजना बनाना।

IAS-PCS Institute

सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन के बिना एक ODF गांव प्रशासनिक रूप से अधूरा और नैतिक रूप से असमर्थनीय है।

निष्कर्ष भारत की स्वच्छता यात्रा के अगले चरण को शौचालयों की गिनती से आगे बढ़कर लचीले सिस्टम बनाने की ओर बढ़ना चाहिए। शहरी-ग्रामीण भागीदारी, जैसा कि सतारा में प्रदर्शित किया गया है, दिखाती है कि सहयोग, जवाबदेही और नैतिक शासन के माध्यम से स्वच्छता परिणामों को स्थायी बनाया जा सकता है। स्वच्छ भारत की वास्तविक सफलता प्रमाण पत्रों या बुनियादी ढांचे से नहीं, बल्कि स्वस्थ समुदायों, संरक्षित पारिस्थितिक तंत्र और सभी के लिए गरिमा से मापी जाएगी।

UPSC मुख्य परीक्षा-उन्मुख अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. लगभग सार्वभौमिक 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) दर्जा प्राप्त करने के बावजूद, ग्रामीण भारत में स्वच्छता की चुनौतियां बनी हुई हैं। स्वच्छता के बुनियादी ढांचे-केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाओं पर चर्चा करें और जांच करें कि शहरी-ग्रामीण भागीदारी स्वच्छता परिणामों को बनाए रखने में कैसे मदद कर सकती है? (250 शब्द)

प्रश्न 2. "शहरी-ग्रामीण अभिसरण को नीतिगत विकल्प के बजाय शासन की आवश्यकता के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है।" स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण चरण II के तहत स्वच्छता सुधारों के संदर्भ में, इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द)

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806